□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 4427
19 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

महाराष्ट्र से प्राप्त स्वास्थ्य परिचया संबं□□ प्रस्ताव

4427. श्री प्रतापराव पाटिल □□□□□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह □□□□□ो □□□ □□□□ि□□

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा कद्र सरकार को स्वीकृति के लिए संस्तुत किए गए स्वास्थ्य परिचया संबंधी प्रस्तावों को कुल संख्या कितनी है;
(ख) प्राप्त हुए प्रस्तावों म से स्वीकृत और लंबित प्रस्तावों को कुल संख्या कितनी है; और
(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने को संभावना है?

□त्त□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(क) से (ग): "जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है" और सभी लोगों को स्वास्थ्य परिचया प्रदानगी को जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार को है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन परिप्रेक्ष्य म प्रस्तावित आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य परिचया प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय एवं तकनीको सहायता प्रदान को जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कायक्रम कायान्वयन योजना (पीआईपी) के रूप म प्रस्ताव प्राप्त किए जाते ह। राष्ट्रीय कायक्रम कायान्वयन समिति (एनपीसीसी) को बैठक म पीआईपी को मंजूरी दी जाती है और कारवाई अभिलेख (आरओपी) दज किया जाता है। विगत तीन वर्षों अथात् वित्त वष 2016-17 से 2018-19 म महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत पीआईपी https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linked=55&lid=68.पर उपलब्ध ह। पीआईपी का मूल्यांकन किया गया था और उपयुक्त वैब लिक पर आरओपी के रूप म गतिविधि अनुमोदन के विवरण उपलब्ध ह।

इसके अलावा “मौजूदा जिला और रेफरल अस्पताल के सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना” के चरण-I के तहत माच, 2015 म महाराष्ट्र म गोंडिया म मेडिकल कॉलेज को स्थापना को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए 189 करोड़ रूपए को अनुमोदित लागत 60:40 अनुपात के रूप म केन्द्र और राज्य के बीच साझा को जानी थी। केन्द्र भाग को 113.40 करोड़ रूपए को राशि राज्य सरकार को निगत कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज प्रचालित कर दिया गया है।

****